भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *61

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

डिंभे बांध नहर परियोजना

*61. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शिरूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में डिंभे बांध नहर परियोजना सहित लंबित सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके विभिन्न चरणों के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि की विस्तृत रिपोर्ट सहित इन परियोजनाओं के लिए किए गए कुल वित्तीय आबंटन और वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा क्या है तथा प्रशासनिक और तकनीकी विलंब, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की हमेशा बनी रहने वाली कमी की समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी दीर्घकालिक योजना बनाई गई है और सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी आर पाटील)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'डिंभे बांध नहर परियोजना' के संबंध में दिनांक 04.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *61 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जल राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, संचालन और प्रबंधन का कार्य संबंधित राज्य सरकार का है। भारत सरकार की भूमिका चल रही योजनाओं के तहत चिन्हित परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, अंतर्राज्यीय नदी प्रणाली पर वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए, इस मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि शिरूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में तीन सिंचाई परियोजना अर्थात् कुकड़ी परियोजना, चिल्हेवाड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना और चस्कमन परियोजना कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

1. कुकड़ी परियोजना: कुकड़ी परियोजना पांच बांधों अर्थात् डिंभे बांध, येडगांव बांध, मानिकदोह बांध, वडाज बांध और पिंपलगांव जोगे बांध और उनके नहर नेटवर्क का एक संयुक्त परियोजना है। इन सभी बांधों के मुख्य नहर का कार्य पूरा हो चुका है। वितरण प्रणाली में शेष कार्य कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में हैं।

डिंभे बांध और उसकी बायीं तट पर नहर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस बांध की दायीं तट पर नहर का निर्माण कार्य 116 कि.मी. में से 102 कि.मी तक पूरा हो चुका है।

2. चिल्हेवाड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना: चैनेज 0 से चैनेज 28/263 तक मुख्य नहर पाइपलाइन का कार्य पूरा हो गया है। चैनेज 28/263 से 39/080 तक का कार्य शेष है।

3. चस्कमन परियोजना: बांध, नहर की मिट्टी की खुदाई (कैनल अर्थवर्क्स) और नहर पर संरचना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बायीं तट की नहर की 144 कि.मी. लंबाई में से, 16 कि.मी. लंबाई की लाइनिंग का कार्य पूरा हो चुका है।

(ख): वर्ष 2002-03 से वर्ष 2008-09 के दौरान कुकड़ी परियोजना और चस्कमन परियोजना के लिए 270 करोड़ रूपए और 95.38 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान में, इन परियोजनाओं को राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से कार्यान्वित कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में तीन परियोजनाओं के लिए बजट और किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

परियोजना का नाम	बजट (करोड़ रुपए में)	व्यय (करोड़ रुपए में)
कुकड़ी परियोजना	757.55	757.55
चिल्हेवाड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना	41.27	41.27
चस्कमन परियोजना	114.98	14.19

(ग): महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना के पूरा होने की संभावित तारीख की सूचना दी है, जो निम्नानुसार है:

परियोजना का नाम	पूरा होने की संभावित तारीख
कुकड़ी परियोजना	मार्च' 2028
चिल्हेवाड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना	जून' 2026
चस्कमन परियोजना	जून' 2029

(घ): देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई के विकास के मुद्दे के समाधान के लिए, पीएमकेएसवाई के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना के चयन का मापदंड और केंद्रीय वित्तपोषण अनुपात में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी परियोजना का 50% से अधिक कमान सूखा प्रवण क्षेत्र में है तब अग्रिम चरण के मापदंड में 50% की छूट दी गई है और सूखा प्रवण क्षेत्र में आने वाले कमान क्षेत्र के अनुपात में चल रही परियोजना को निर्माण की शुरुआत से ही शामिल किया जा सकता है, जिसमें 60 (केंद्र): 40 (राज्य) का बढ़ा हुआ वित्तपोषण अनुपात होगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सूखे प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाले 63 वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना को शामिल किया गया है, जिनमें से 16 परियोजना महाराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं। वर्ष 2016 से भारत में सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाले परियोजना में 16.40 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है, जिसमें से 3.10 लाख हेक्टेयर महाराष्ट्र में है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजना के लिए एक विशेष पैकेज को मंज़ूरी दी है, ताकि विदर्भ और मराठवाड़ा के सूखा प्रवण जिलों और शेष महाराष्ट्र में 83 सतही सूक्ष्म सिंचाई (एसएमआई) परियोजना और 8 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 67 एसएमआई और 3 एमएमआई कार्य पूरे हो चुके हैं और 2.16 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और महाराष्ट्र पैकेज के अंतर्गत महाराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना देश में सूक्ष्म सिंचाई के विकास के लिए समर्पित है। वर्ष 2015-16 से अब तक 106.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया गया है, जिसमें से 11.83 लाख हेक्टेयर महाराष्ट्र राज्य में है।

इस मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने लगभग 25 लाख वर्ग कि.मी. के संपूर्ण मापन योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (नैक्यूम) परियोजना पूरा कर लिया है। जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन योजना तैयार कर ली गई है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। इस प्रबंधन योजना में मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के माध्यम से जल संरक्षण के अलग-अलग उपाय शामिल हैं।

इसके अलावा, "जल शक्ति अभियान", "जल संचय जन भागीदारी" इस मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण में जन भागीदारी के साथ शुरू की गई पहल हैं, जिसमें सरकारी निकाय, उद्योग, स्थानीय प्राधिकरण, समाजसेवी, आवासीय कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) और लोग सहित सभी हितधारकों की एकजुट कार्रवाई शामिल है।

*****

अनुलग्नक

'डिंभे बांध नहर परियोजना' के संबंध में दिनांक 04.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *61 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और महाराष्ट्र पैकेज के अंतर्गत महाराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं का विवरण

क. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी				
करोड़ रुपए में				
क्र. सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिला	जारी केंद्रीय सहायता (वर्ष 2016-25)	टिप्पणी
1	निचला पंजारा परियोजना	धुले	18.62	पूर्ण
2	डोंगरगांव परियोजना	चंद्रपुर (वी)	5.88	पूर्ण
3	नंदुर मध्मेश्वर चरण-II परियोजना	औरंगाबाद (एम)	17.24	पूर्ण
4	ऊपरी कुंडलिका परियोजना	बीड (एम)	10.92	पूर्ण
5	खड़कपूर्णा परियोजना	बुलढाणा (वी)	40.16	पूर्ण
6	धोम बालाकवाड़ी परियोजना	पुणे/सतारा	51.06	पूर्ण
7	कृष्णा कोयाना लिफ्ट सिंचाई परियोजना	सोलापुर, सांगली	303.86	पूर्ण
8	ताराली परियोजना	सतारा	72.06	पूर्ण
9	संगोला शाखा नहर परियोजना	सोलापुर,	32.43	पूर्ण
10	बेम्बला परियोजना	यवतमाल (वी)	307.17	पूर्ण
11	अपर पेन गंगा परियोजना	यवतमाल (वी), (नांदेड़ (एम), हिंगोली	207.27	पूर्ण
12	वाघुर परियोजना	जलगांव	195.02	चल रही
13	लोअर पेढ़ी परियोजना	अमरावती (वी), अकोला (वी)	19.56	चल रही
14	गोसीखुर्द परियोजना	नागपुर (वी), भंडारा (वी), चंद्रपुर (वी)	893.34	चल रही
15	जिहे कथापुर परियोजना	सतारा	207.75	चल रही
16	बोडवाड परिसर सिंचन योजना चरण-I	जलगांव, बुलढाणा	0.00	चल रही
कुल			2382.34	

ख. महाराष्ट्र पैकेज (एमएमआई)				
करोड़ रुपए में				
क्र. सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिला	जारी केंद्रीय सहायता (वर्ष 2018-25)	टिप्पणी
1	तेम्भू एलआईएस	सतारा, सांगली, सोलापुर	297.16	पूर्ण
2	शेलगांव बैराज मध्यम परियोजना	जलगांव	135.26	पूर्ण
3	घुंग्शी बैराज एलआईएस	अकोला (वि.)	37.72	पूर्ण
4	उर्मोदी परियोजना	सतारा	38.25	चल रही
5	सुलवाडे जामफल कनोली एल.आई. योजना	धुले	464.15	चल रही
6	पूर्णा बैराज नंबर 2 (नेरधामना)	अकोला (वि.)	16.55	चल रही
7	जिगांव परियोजना	बुलढाणा (वी), अकोला (वी)	1176.05	चल रही
8	वारखेड लोंढे परियोजना	जलगांव	88.79	चल रही
कुल			2253.93	

ग. महाराष्ट्र पैकेज (एसएमआई)				
करोड़ रुपए में				
क्र. सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिला	जारी केंद्रीय सहायता (वर्ष 2018-25)	टिप्पणी
1	विदर्भ (66)	अमरावती (18), अकोला (7), वाशिम (18), यवतमाल (14), बुलढाणा (8), वर्धा (1)	656.04	58 पूर्ण
2	मराठवाड़ा (17)	औरंगाबाद (5), जालना (6), नांदेड़ (2), लातुर (3), बीड (1)	114	9 पूर्ण
कुल			770.04	

नोट: वी: विदर्भ, एम: मराठवाड़ा

*****